



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2018/वैशाख 3, 1940

No. 145]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23 2018/ VAISAKHA 3, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पी ओ वाई) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

**फा- सं. 7/01/2017 – डी जी ए डी.**—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क तथा क्षति के निर्धारण के लिए पहचान, आकलन और संकलन) नियमावली 1995 (इसके पश्चात पाटनरोधी नियमावली के रूप में भी संदर्भित), निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. (इसके पश्चात संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पी ओ वाई), (इसके पश्चात संबद्ध वस्तु/ विचाराधीन उत्पाद/ पी यू सी के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना को दिनांक 08 जून, 2007 को अधिसूचना 14/10/2005 – डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित की थी। इस जांच परिणाम के आधार पर, संबद्ध देशों से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2007 के अधिसूचना संख्या 92/2007 के माध्यम से लगाये गए थे।

- बाद में, प्राधिकारी ने दिनांक 11 फरवरी, 2011 के अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की और दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 15/27/2010 - डी जी ए डी के माध्यम उपर्युक्त देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाने की सिफारिश की। इन शुल्कों को आगे 5 वर्षों की

अवधि के लिए अर्थात् 1 मई, 2017 तक दिनांक 2 मई, 2012 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 22/2012 – सीमा शुल्क (पाटन रोधी शुल्क) से बढ़ाया गया था।

3. जबकि, सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के संबंध में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को यदि पूर्व में निरस्त नहीं किया जाता है तब इसका प्रभाव इस प्रकार के लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत पुष्ट किए गए अनुरोध के पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
4. जबकि, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड (इसके पश्चात् “याचिकाकर्ता अथवा आवेदक” के रूप में संदर्भित) द्वारा इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए उपर्युक्त वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का आरोप लगाते हुए आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए इन शुल्कों का विस्तार करने के लिए आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पी ओ वाई) के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा आरंभ करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।
5. और जबकि, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुसार इस बात की जांच करने के लिए संबद्ध जांच आरंभ करने के लिए अधिसूचना संख्या 07/01/2017 – डी जी ए डी दिनांक 28 अप्रैल, 2017 जारी किया, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया कि क्या संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात पर उक्त शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए उपर्युक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

#### क. प्रक्रिया

7. यहां नीचे उल्लेख की गई प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है
  - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी की निर्णायक समीक्षा से संबंधित आवेदन से प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया है।
  - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करते हुए दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के तथा घरेलू उद्योग के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को, भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार जांच आरंभ संबंधी अधिसूचना की एक प्रति उपलब्ध कराई और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच आरंभ संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर निश्चित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।
  - iv. प्राधिकारी चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को संबंधित सूचना देने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों को अवगत कराने के लिए अवसर प्रदान किया।
    1. केमिकल फाइबर्स एसोशिएशन
    2. सिक्सी सनतेई केमिकल फाइबर कं. लिमि.
    3. झीजियांग सीफू केमिकल फाइबर कं. लिमि.
    4. डब्ल्यू. डब्ल्यू टेक्सटाइल कं. लिमि.

5. ज़ेंगझोउ हाउझिंग टेक्सटाइल कं. लिमि.
  6. झिंझियांग सनशाइनिंग टेक्सटाइल कं. लिमि.
  7. टाँगकुंग ग्रुप झिजियांग हेंगसेंग केमिकल फाइबर कं. लिमि.
  8. ज़ेंगझोउ झॉंगली केमिल फाइबर कं. लिमि.
- v. हालांकि संबद्ध देश के किसी उत्पादक/ निर्यातक ने उपर्युक्त मामले में प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- vi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों (जिनके नाम और पते इस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी अग्रेसित की और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी।
1. सनटेक्स इण्डिया
  2. ग्लेक्सी टेक्सटाइल्स
  3. हार्मोनी यार्न प्रा. लिमि.
  4. ए वी एम एक्सपोर्ट
  5. गर्ग टेक्स-ओ-फेब लिमि.
  6. बोगहारा पोलिफेब प्रा. लिमि.
  7. सिल्वासा इंडस्ट्रीज लिमि.
  8. वीकेलन सेंथेटिक्स लिमि.
  9. अलोक इंडस्ट्रीज लिमि.
  10. बजराई फिलामेंट प्रा. लिमि.
  11. सिदवन यार्न लिमि
  12. क्रिमप्लॉन यार्नस
  13. उनी टेक्स टेक्सटेक्सटरीसर्ज
  14. यूनिफी टेक्सचर्स
  15. घूमटेक्स (इण्डिया) प्रा. लिमि.
  16. मेहराटेक्स इण्डिया प्रा. लिमि.
  17. एस आर वी पोलिटेक्स प्रा. लिमि.
  18. सिनफेब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- vii. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों ने उपर्युक्त मामले में प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तरों/ अनुरोधों को प्रस्तुत किया है :
1. ऑल इण्डिया टेक्सटेक्सर्स' एसोसिएशन
  2. भूमि यार्नस प्रा. लिमि.
  3. यूनिफी टेक्सटेक्सर्स प्रा. लिमि.
  4. शेखावती पोलि यार्न लिमिटेड
- viii. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक याचिका के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

- ix. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक की है।
- x. जांच की अवधि याचिकाकर्ता द्वारा जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 (12 महीने) के रूप में प्रस्तावित थी। हालांकि, प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) के रूप में जांच की अवधि पर विचार करने के बाद जांच करने के लिए इसे अधिक उपयुक्त माना। क्षति संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।
- xi. इसके अलावा, आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक इसे जांच के उद्देश्य से आवश्यक समझा गया।
- xii. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने तथा उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है जिससे की यह पता चल सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. लेन देन वार आंकड़े वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से मांगे गए थे और उसे भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार मौखिक रूप से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के वास्ते 22 फरवरी, 2018 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था।
- xv. सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि ये विरोधी पक्षकारों द्वारा दिए गए लिखित अनुरोधों को प्राप्त करें और यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उसके बाद अपने प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें।
- xvi. निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना की आपूर्ति की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की अवधि के दौरान किए गए अनुरोधों को जहां भी उपयुक्त पाया गया उसका समाधान प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में किया गया है।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- xix. इस प्रकरण विवरण में \*\*\* गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना का द्योतक है।
- xx. प्राधिकरण द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 67.95 रुपये है।

**विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु****घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

8. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध निम्नानुसार है :

- i. विचाराधीन उत्पाद आंशिक रूप से उन्मुख यार्न है, जिसे सामान्य तौर पर पी ओ वाई के रूप में जाना जाता है। यह पोलिस्टर का यार्न है और एक मध्यवर्ती है, जो आगे प्रसंस्करण किए जाने के अधीन है, उदाहरण के लिए टेक्चर बनाने और ट्विस्टिंग किए जाने के अधीन ताकि यह फेब्रिक्स में बुनाई अथवा नीटिंग के लिए उपयुक्त हो सके। यह निर्यात और आयात मर्दों के सीमा शुल्क शीर्षक 5402.4600 आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।
- ii. आयात किए उत्पाद का आयात स्पष्ट रूप से दिए गए शीर्षक के अलावा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत भी किया जाता है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी द्वारा अपना गई प्रथा के अनुसार, सीमा शुल्क शीर्षक केवल सांकेतिक हैं और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र उस क्षेत्र से नहीं बदला जा सकता है जो मूल जांच में था।

**उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

9. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई टिप्पणी/ अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

10. विचाराधीन उत्पाद आंशिक रूप से उन्मुख यार्न है, जिसे सामान्य तौर पर पी ओ वाई के रूप में जाना जाता है। यह पोलिस्टर का यार्न है और एक मध्यवर्ती है, जो आगे प्रसंस्करण किए जाने के अधीन है, उदाहरण के लिए टेक्चर बनाने और ट्विस्टिंग किए जाने के अधीन ताकि यह फेब्रिक्स में बुनाई अथवा नीटिंग के लिए उपयुक्त हो सके।
11. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण अध्याय शीर्षक 54024600 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं का आयात अन्य शुल्क शीर्षकों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। इसके अलावा सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
12. चूंकि वर्तमान जांच लागू शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जिसकी परिभाषा मूल जांच में दी गई है।
13. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-  

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
14. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद में कोई अधिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद बौद्धिक विशेषताओं उत्पादन प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन के मामले में आयात किए गए संबद्ध उत्पाद से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं।
15. प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से भारत में आयात किए गए संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय के अनुसार समान वस्तु हैं।

**घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार****घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

16. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है :

- i. निर्णायक समीक्षा याचिका मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इसका विधिवत समर्थन मैसर्स इण्डो रामा सिंथेटिक्स (इण्डिया) लिमि. मैसर्स जे बी एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लिमि और मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- ii. याचिकाकर्ता और समर्थक संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। यद्यपि नियम 5 निर्णायक समीक्षा जांचों पर लागू नहीं है फिर भी आवेदक और समर्थक एक साथ घरेलू उद्योग की स्थिति को उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।
- iii. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से (या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) संबंधित नहीं है। इस प्रकार से याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

**उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

17. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार के संबंध में कोई टिप्पणी/ अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

18. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. वर्तमान मामले में आवेदन मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमि. द्वारा दायर किया गया है और इसका समर्थन मैसर्स इण्डो रामा सिंथेटिक्स (इण्डिया) लिमि. मैसर्स जे बी एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लिमि और मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है।
20. यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता इन समर्थकों के साथ संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होता है। प्राधिकारी ने जांच आरंभन के चरण में यह निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता इन समर्थकों के साथ साथ संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक होने के कारण इस नियमावली के अंतर्गत स्थान की आवश्यकता को पूरा किया और याचिकाकर्ता इस नियमावली के अभिप्राय के अनुसार घरेलू उद्योग होता था। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने नियम 5(3) के अंतर्गत स्थान की आवश्यकता को पूरा किया और नियम 2(ख) के अभिप्राय के अनुसार घरेलू उद्योग होता है।

**गोपनीयता से संबंधित मुद्दे****घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

21. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

- i. याचिकाकर्ता ने केवल इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया है जिसकी गोपनीयता की अनुमति इस नियमावली के अंतर्गत और प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार दी गई है।

- ii. याचिकाकर्ता ने आवेदन का अपर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना के किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में सक्षम नहीं हो पाया है जिसका दावा गोपनीय के रूप में किया गया है और जिसकी गोपनीयता इस नियमावली के अंतर्गत न्यायोचित नहीं है।
- iii. भारत में निर्यात की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री की सकल मात्रा, उत्पादन, बिक्री, भारत में निर्यात के लिए औसत कीमत जैसी सूचना सूचीबद्ध पाठ में उपलब्ध कराया गया है क्योंकि यह सूचना बिजनेस प्रोप्राइटी सूचना है।

### **उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

22. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान गोपनीयता के संबंध में उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- i. इस याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई है। इस याचिका में मांग के संबंध में पूर्ण रूप से कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार के सूचना के होने से उचित मात्रा प्रभाव विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
  - ii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है और इसे इस अर्थ में अत्यधिक गोपनीयता की अनुमति दी गई है कि उन्होंने सार्वजनिक फाइल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है।
  - iii. घरेलू उद्योग ने अपनी लागत का पर्याप्त ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक याचिका के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

#### ***"गोपनीय सूचना"***

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

25. पाटनरोधी संबंधी विश्व व्यापार संघठन के करार में सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है :

"अनुच्छेद - 6.5 कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति के हों (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतियोगी के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करेगा अथवा क्योंकि इसका प्रकटन की सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर जिससे उस व्यक्ति में सूचना प्राप्त की पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा) अथवा जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, में दर्शाये गये सही कारण से उसे

प्राधिकारियों द्वारा उस प्रकार से माना जायेगा। इस प्रकार की सूचना को इसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद – 6.5.1 प्राधिकारी गोपनीय सूचना उपलब्ध कराने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। ये सारांश विश्वस्त में प्रस्तुत की गई सूचना के मूल भाव को सही ढंग से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण के साथ होगा। आपवादिक स्थितियों में ऐसे पक्षकार यह दर्शायेंगे कि इस प्रकार की सूचना के सारांश पर संदेह नहीं हो सकता है। इस प्रकार आपवादिक स्थितियों में, कारणों का एक विवरण कि क्यों सारांश दिया जाना संभव नहीं है अवश्य दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद – 6.5.2 यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है और यदि इस सूचना के आपूर्तिकर्ता या तो उस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना उस स्थिति में नहीं मान सकता है जब उनकी संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्रोतों से यह दर्शाया जा सकता है कि यह सूचना सही है।

अनुच्छेद 6.5.2 के फुटनोट (पाटनरोधी संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करार के फुटनोट 18) में निम्नानुसार व्यवस्था है : सदस्य इस बात पर सहमत होते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध को एक तरफ से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।”

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

### **अन्य विविध मुद्दे**

#### **घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

27. जहां तक पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद शुल्कों को बढ़ाये जाने की कानूनी वैधता का प्रश्न है यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादी पक्षकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात को समझें कि पाटनरोधी शुल्कों इस मामले में केंद्र सरकार अर्थात् वित्त मंत्रालय द्वारा लगाये गये हैं। यदि उनके पास ऐसा कोई मुद्दा बिलकुल है ही नहीं तब कानूनी अथवा अन्य प्रकार से शुल्कों का समय विस्तार की कानूनी वैधता के संबंध में, उन्हें उपयुक्त मंच के पास जाना चाहिए था। इस मुद्दे को निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान नहीं उठाया जा सकता है। यह नोट करना संगत है कि वाद कानून जिस पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा विश्वास किया गया है धारा 9(क)(5) के दूसरे उपबंध और न कि सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9(क)(5) के प्रथम उपबंध की व्याख्या करने के संदर्भ में हैं।
28. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इन शुल्कों का समय विस्तार 10 वर्षों की अवधि के आगे नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'ड्राई सेल बैट्री' के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर विश्वास किया है। हालांकि, उक्त अनुच्छेद को केवल पढ़ने मात्र से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की निर्भरता सही नहीं है। प्राधिकारी की उपर्युक्त टिप्पणी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन शुल्कों को उस समय सीमा के आगे नहीं बढ़ाया जाता है जहां तक यह अपेक्षित है। कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो इस बात का सुझाव देता हो कि वर्षों की संख्या पर किसी प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क सुरक्षा किसी उद्योग को दी जानी चाहिए। धारा 9(क)(5) के प्रावधान इस मुद्दे के संबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। यह सच है कि पाटनरोधी शुल्कों को भारत में अनेक मामलों में 10 वर्षों से अधिक समय तक जारी रखा गया है। वर्तमान मामले में यह तथ्य की वर्तमान पाटन और क्षति मौजूद है इस बात को सिद्ध करता है कि शुल्कों को हटाया जाना याचिकाकर्ता सहित संबद्ध वस्तुओं के घरेलू निर्माता के लिए खतरनाक होगा।



29. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि याचिकाकर्त्ता सहित पी ओ वाई के निर्माता पी ओ वाई की बिक्री पर बहुत अधिक लाभ कमाते हैं जबकि पी टी वाई जो एक डाउन स्ट्रीम उत्पाद है की बिक्री अलाभप्रद और बहुत कम मार्जिन के साथ निम्न कीमतों पर करना होता है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त दावे पूर्ण रूप से आधारहीन हैं और सत्यता से काफी दूर हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पहले ही घरेलू सत्यापन किया है और इसने पहले ही यह दर्शाया है कि याचिकाकर्त्ता सहित घरेलू पी ओ वाई निर्माता गैर-लाभप्रद कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस बात का दावा करना बिलकुल सही नहीं है कि घरेलू निर्माता पी ओ वाई की बिक्री से बहुत अधिक लाभ कमाते हैं।
30. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि पी टी वाई की कृत्रिम रूप से निम्न कीमतों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे भी पूर्ण रूप से आधारहीन हैं। सच यह है कि पी टी वाई की बिक्री परिवर्तन लागत को ध्यान में रखने के बाद लाभकारी है। प्रतिवादी पक्षकार इस बात को समझ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि याचिकाकर्त्ता और समर्थकों के पास एकीकृत उत्पादक होने के कारण पी टी वाई बिजनेस के संबंध में कुछ लाभ हैं। इसे इस तथ्य से दर्शाया गया है कि एकीकृत उत्पादकों ने एकीकृत उत्पादकों की अंतरनिहित क्षमताओं के बल पर ही स्वतंत्र उत्पादकों की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि देखी है। यह भी उल्लेख करना संगत है कि पिछले कुछ वर्षों में टेक्सचर बनाने वाली इकाईयों ने भी अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने अन्य कारकों को प्रकट नहीं किया है जो उच्चतर बिजली लागतों, कराधान संबंधी मुद्दों आदि के संबंध में अपने खराब कार्य निष्पादन में योगदान कर रहे होंगे। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों के इस संबंध में किए गए दावे पूर्ण रूप से आधारहीन हैं।
31. जहां तक इन दावों का प्रश्न है कि पी टी वाई/ पोलियस्टर फेब्रिक का निर्माण करने के लिए कच्चे माल को पाटनरोधी शुल्कों से हानि उठानी पड़ती है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादियों के दावे सही नहीं हैं। पोलियस्टर फेब्रिक का निर्माण करने के लिए अपेक्षित एम ई जी और पूर्ण रूप से निकाले गए यार्न पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है। इसके अलावा, उसको छोड़कर स्रोतों से आयात किए गए पी टी ए पर भी कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है। घरेलू उद्योग के अनुसार, प्रतिवादियों ने प्राधिकारी को यह नहीं बताया है कि फेब्रिक्स के उत्पादन पर चीन से आने वाले अपेक्षाकृत सस्ते और पाटित फेब्रिक्स के कारण और न की कच्चे मालों पर पाटनरोधी शुल्कों की किसी घटना के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस तथ्य का संज्ञान लेकर सरकार ने अक्टूबर 2017 से फेब्रिक्स पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।
32. यह भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि फेब्रिक्स के निर्यात पर प्रतिबंध पी ओ वाई पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के कारण हुआ था। सबसे पहले निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के परियोजन से कच्चे माल का कोई आयात को छूट दी गई है और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्कों को नहीं लगाया जायेगा। दूसरा, तैयार उत्पादों का घरेलू प्रयोक्ता तथा निर्यातक अनेक अन्य स्रोतों से पी ओ वाई का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं जो पाटनरोधी शुल्कों अधीन नहीं हैं। यह भी नोट किया जा सकता है कि एस आर टी ई पी सी (संश्लेषित एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रामेशन काउंसिल), भारत सरकार के अनुसार, फेब्रिक्स के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पी टी वाई के निर्यात में 2014-15 और 2016-17 के बीच लगभग 34 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस कारण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं तथ्यात्मक रूप में सही नहीं हैं और इन्हें तत्काल अस्वीकार किया जाना चाहिए।

### **विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण**

33. वर्तमान मामले में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 1 मई, 2017 को समाप्त हो गया और वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 16/2017 – सीमा शुल्क (पाटनरोधी शुल्क) ने निर्णायक समीक्षा के अंतरिम काल के लिए शुल्क का समय विस्तार करते हुए 9 मई, 2017 को ही जारी किया गया था। यह स्थापित कानून है कि जहां सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसरण में एक निर्धारित समय अवधि का विस्तार किया जाना अपेक्षित हो, तब उसे निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से मूल समयावधिक के समाप्त होने पर अथवा उसके पहले अवश्य किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए आरंभिक अधिसूचना के समाप्त होने के पूर्व पाटनरोधी

शुल्क की अधिसूचना का समय विस्तार नहीं दिया गया था। इस कारण से यह शुल्क समय के समाप्त होने के कारण लागू नहीं रहा है। उपर्युक्त नियम के आलोक, पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान मामले में समय विस्तार गैर-कानूनी है।

34. वर्तमान समीक्षा में, मूल जांच दिसंबर, 2005 में शुरू की गई थी और जून 2007 में शुल्क लगाया गया था। इस प्रकार से संबद्ध वस्तु पर 10 वर्षों से अधिक तक पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है। वर्तमान मामले के आवश्यक तथ्य पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने की आवश्यकता को देखते हुए किसी विशेष परिसरितियों में प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'ट्राइसेल बैट्रियों' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी की निर्णायक समीक्षा में दिनांक 20 मई, 2013 के प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम से यह सिद्धांत सामने आता है जहां प्राधिकारी ने यह माना है कि :

*“प्राधिकारी का यह प्रयास है कि विशेष मामलों जहां प्राधिकारी यह महसूस करते हैं कि अलग अलग मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क पूर्ण रूप से आवश्यक है, को छोड़कर 10 वर्षों से अधिक तक पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जायेगा।”*

35. घरेलू उद्योग ने मूल जांच में शुल्क लगाये जाने के समय से पाटनरोधी महानिदेशालय से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त की है। इस सुरक्षा को आगे अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क को जारी रखकर कराया गया था। हम नोट करते हैं कि पहली निर्णायक समीक्षा के समाप्त होने पर भी, प्राधिकारी ने नकारात्मक क्षति मार्जिन पाया था। अतः घरेलू उद्योग का नकारात्मक आर्थिक मापदण्ड जिससे मूल आरोपन आवश्यक हो गया था, पहले ही पांच साल पूर्व लागू होना बंद हो गया था। ऐसे तथ्यों के बावजूद कोमा प्राधिकारी ने शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की थी। हालांकि, वर्तमान मामले में क्षति के लगातार न होने का साक्ष्य याचिकाकर्ता के कार्य निष्पादन मानदण्डों के मिलता है और इस कारण से प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
36. आंशिक रूप से उन्मुख यार्न पोलियस्टर टेक्सचर्ड यार्न (पी टी वाई) जो पूर्ण रूप से निकाला गया, पूर्ण रूप से उन्मुख पोलियस्टर एकल अथवा बहु फिलामेंट यार्न है जिसमें कॉटन फील और बहुत अधिक टिकाउपन और अवधारणा संबंधी लक्षणों के साथ सॉफ्ट क्रिम्प, अत्यधिक बलक है, का निर्माण करने के लिए कच्चा माल है। इसका निर्माण अत्यधिक गति वाले टेक्सचर बनाने वाले मशीनों का उपयोग करते हुए टेक्सचर बनाने वाले पी ओ वाई द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता की तरह ऐसे अनेक सी ओ वाई निर्माता हैं जिन्होंने डाउन स्ट्रीम पी टी वाई के निर्माण के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं। ये उत्पादक बहुत कम मार्जिन के साथ अलाभप्रद और निम्न कीमतों पर पी टी वाई की बिक्री करते समय पी और वाई की बिक्री पर बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। वास्तव में इस प्रकार उत्पादकों के पी ओ वाई और पी टी वाई के बीच कीमत में अंतर टेक्सचर बनाने वाली पी ओ वाई में निहित निर्माण की लागत शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टेक्सराइजर बाजार में बने रहने में सक्षम नहीं हैं और उनके बाजार शेयर होलिंग में 75 प्रतिशत से अधिक से 25 प्रतिशत से कम तक गिरावट आई है।
37. पाटनरोधी शुल्क केवल कुछ चयनित बिजनेस जो याचिकाकर्ता का है, जो सबसे अधिक कार्यक्षम होने का दावा करते हैं और समग्र कच्चे माल की श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, को लाभ पहुंचाता है। हालांकि, इन शुल्कों को लगाने के फलस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योगों को क्षति होती है जिसमें टेक्सराइजिंग/ निटिंग/ विडिंग/ प्रॉसेसिंग/ गार्मेंटिंग और सभी सहायक उद्योग शामिल हैं जो सामूहिक रूप से इस देश में दूसरे सबसे बड़े रोजगारदाता हैं और उनका इस शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में रोजगार को और अधिक देने के लिए पर्याप्त अवसर है। प्यूरी फाइड टेरपेथेलेटिक एसिड/ मोनो एथिलेन ग्लाइकोल/ आंशिक रूप से उन्मुख यार्न/ पूर्ण रूप से निकाली गई यार्न – पोलियस्टर फेब्रिक का निर्माण करने के लिए अपेक्षित सभी कच्चे माल पर 5.5 प्रतिशत सीमा शुल्क और 5 सेंट से 50 सेंट प्रति किलोग्राम तक पाटनरोधी शुल्क लगता है जो फेब्रिक को अंतर्राष्ट्रीय फेब्रिक की तुलना में अप्रतियोगी बना देता है जो बाद में काफी सीमा तक फेब्रिक्स और गार्मेंट के निर्यात को प्रतिबंधित करता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

38. हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क 1 मई, 2017 को समाप्त हो गया जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा समय विस्तार 9 मई, 2017 को दिया गया था और इस कारण से शुल्कों का यह विस्तार

गैर-कानूनी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच प्राधिकारी द्वारा प्रभावी शुल्कों के समाप्त होने के पूर्व शुरू किया गया था। इस संदर्भ में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स के मामले पर विश्वास किया गया है। प्राधिकारी ने इस संदर्भ में इन अनुरोधों को देखते हुए उक्त निर्णय की जांच सावधानी से की है। उक्त मामले को करने से यह स्पष्ट होता है कि शुल्क के समाप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क के लिए समय विस्तार दिए जाने के बीच अंतर है। इस प्रकार के अंतर के बावजूद निर्णायक समीक्षा जांच को रद्द नहीं किया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुमति दी गई थी कि वे अपने जांच परिणामों को रिकार्ड करें। जिसे स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। स्पष्ट रूप से एक वर्ष तक शुल्कों के विस्तार में किसी अंतर को धारा 9क(5) के प्रावधान के अंतर्गत प्रथम उपबंध के अधीन शुल्कों का समय विस्तार करने संबंधी अधिसूचना के मुद्दे के लिए घातक नहीं माना गया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि यदि हितबद्ध पक्षकारों की वर्तमान अधिसूचना की वैधानिकता के संबंध में कोई मुद्दा हो, तो वे इस मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी उपयुक्त मंच पर जा सकते हैं।

39. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का प्रश्न है कि इन शुल्कों को 10 वर्ष से आगे लागू नहीं किया जा सकता है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं रही है कि शुल्कों को 10 वर्षों की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। शुल्कों को लगाना किसी खास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाना है।
40. जहां तक डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर प्रभाव के संबंध में दिए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की विषय वस्तु आंशिक रूप से उन्मुख यार्न की निर्णायक समीक्षा है जिसे नियम 23 के अंतर्गत शासित किया जाता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम को अपनाकर और अनुबंध III के नियमों को लागू कर, क्षतिरहित कीमतों का निर्धारण करते समय प्राधिकारी प्रयोक्ता उद्योग और आवेदक उद्योग पर किसी क्षति कारक प्रभाव को पूर्ण रूप से संतुलित करते हैं। इस कारण से यह कहना सही नहीं होगा कि प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग यह सिद्ध करने में भी सफल नहीं हो पाया है कि इस मामले में शुल्कों को जारी रखने से आम हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत में किए गए सभी आयात अग्रिम अधिकरण के अंतर्गत किए जाते हैं जिसका दावा घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है।
41. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में की पाटनरोधी शुल्क निर्यात को गैर-प्रतियोगी बनाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रकार के तर्कों में कोई दम नहीं है। निर्यात किए जाने वाली वस्तु के उपयोग के उद्देश्य से ये आयात किसी पाटनरोधी शुल्क से मुक्त हैं। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन के प्रभाव को समाप्त करने तथा घरेलू निर्माताओं एवं निर्यातकों के लिए एक समान अवसर पैदा करने के तक सीमित है। पाटनरोधी शुल्क किसी भी प्रकार से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात समुचित कीमतों पर नहीं हो सका। इस कारण से इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नहीं माना जा सकता है।

### **सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

#### **सामान्य मूल्य**

42. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री औषध सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

### **घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

43. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध निम्न प्रकार से है :

- i. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में पूर्ण सूचना प्रस्तुत की है जो जांच आरंभ करने के उद्देश्य से आवश्यक थी। इसके अलावा, सभी आवश्यक साक्ष्य भी सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के दावे के समर्थन में उपलब्ध कराये गये हैं।
- ii. चीन को पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा तथा अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुरूप एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है।

### **विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण**

44. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य के संबंध में कोई टिप्पणी/ अनुरोध नहीं किया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

45. जांच आरंभ करने के चरण में प्राधिकारी ने एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन जन. गण. को मानकर कार्यवाही शुरू की है। जांच आरंभ करने पर प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने की सूचना का उत्तर देने और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए चीन में उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह दी। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को एम ई टी के प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दें। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

46. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

### **चीन जन. गण. के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

47. संबद्ध देश में तथा किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए किसी विश्वसनीय कीमत और लागत विवरण के अभाव में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समान उत्पाद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तय किया है जिसमें उचित लाभ मार्जिन है। तदनुसार, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तय किया गया है और उसे नीचे दिए गए पाटन मार्जिन तालिका दर्शाया गया है।

### **चीन जन. गण. के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर दिया है। चीन जन. गण. सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत तय की है और उसे नीचे दिए गए पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**पाटन मार्जिन**

49. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण तय किए गए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत की तुलना करने के बाद की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए इस प्रकार से गणना की गई पाटन मार्जिन को दर्शाता है।

क्र. सं.	देश	उत्पादक/ निर्यातक	सामान्य मूल्य (रु./ मी. ट.)	निवल निर्यात कीमत (रु./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (रु./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	रेंज %
1	चीन	सभी निर्यातक/ उत्पादक	****	****	****	****	30-40

50. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन संबद्ध देश के आयातों के लिए न्यूनतम से अधिक है।

**क्षति के आकलन और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति****घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

51. घरेलू उद्योग वर्तमान जांच की अवधि के दौरान किए गए क्षति से संबंधित अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि दर्शायी है। आयातों ने भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि दर्शायी है;
  - लागू पाटन शुल्कों के बावजूद, मांग में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में अभी भी वृद्धि हो रही है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है;
  - चीन के उत्पादकों द्वारा, इन कीमतों में कटौती के साथ, भारतीय उत्पादक के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि वह या तो आयात कीमतों में परिवर्तनों के साथ अपनी कीमतों को समायोजित करें अथवा आदेश को खो दे और इस कारण से बाजार हिस्से को खो दे;
  - घरेलू उद्योग की कीमतें, इन कीमतों के प्रभाव को दर्शाती हैं जिसकी पेशकश आयातकों द्वारा घरेलू बाजार में की जा रही है;
  - कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और वास्तविक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के कारण क्षति उठानी पड़ रही है क्योंकि वे उचित स्तर पर अपनी कीमतों को बनाने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए मुख्य कारण चीन से कम कीमत पर किया गया आयात और वह भी पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर किया गया आयात है;
  - घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के मामले में बहुत अधिक सीमा तक नकारात्मक रही है;
  - बिक्री की कीमत में यह कमी उत्पादन की लागत में कमी की तुलना में अधिक थी और इस प्रकार से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ रहा है;
  - घरेलू उद्योग को चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को वर्तमान स्थिति जारी रहने पर सतत क्षति का खतरा है।

**उत्पादक/ निर्यातक/ आयातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

52. घरेलू उद्योग वर्तमान जांच की अवधि के दौरान किए गए क्षति से संबंधित अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- i. घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही है और इसमें सुधार हुआ है।
  - ii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा याचिकाकर्ता के आवेदन के आधार पर शुरू किया गया है जिसका भारतीय उत्पादन में केवल 28 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे मामले में, क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के ऐसे लघु और बिना प्रतिनिधि वाले खण्ड के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता।
  - iii. याचिकाकर्ता की क्षमता के साथ साथ इसके समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है हालांकि, बड़ी हुई क्षमता के कारण इसके क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि के मध्य काल में गिरावट आई। इस कारण से याचिकाकर्ता की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के आधार पर क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है।
  - iv. याचिकाकर्ता धीरे धीरे कुल मांग में गिरावट के बावजूद क्षति की अवधि में मांग में अपने बाजार हिस्से में वृद्धि की।
  - v. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं से कीमत और मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
  - vi. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने कीमत में कटौती के लिए भी कोई दावा नहीं पेश किया है। याचिकाकर्ता ने केवल कम कीमत पर वृद्धि का आरोप लगाया है।
  - vii. क्षति और जांच की अवधि में चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा भारतीय उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और भारतीय मांग की तुलना किए जाने पर बहुत कम है।
  - viii. बल्कि, 2014-15 से आगे के आंकड़ों पर विचार करते हुए, वर्ष 2015-16 में आयातों की मात्रा में 10156 मी. ट. से 10491 मी. ट. और अंत में जांच की अवधि के दौरान एक 8523 मी. ट. तक गिरावट हुई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि के लिए अनुमान उपर्युक्त आंकड़ों से प्राप्त किए जाने वाले तार्किक निष्कर्ष नहीं होगा। आयात की मात्रा में स्वतंत्र रूप में वृद्धि के कारण हो रही क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे का कोई आधार नहीं है।
  - ix. घरेलू उद्योग पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की किसी संभावना को सिद्ध करने में असफल रहा है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

53. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के संबंध में की जानी है।
54. यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वर्तमान जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों का समाधान करता है।
55. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III और पाटनरोधी महानिदेशालय की स्थापित परंपराओं के अनुसार क्षति रहित कीमत की गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।
56. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II(iv) के अनुसार ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिसका उद्योग की हालत जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मात्रा पर प्रभाव पड़ता हो।

**क. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव****आयात की मात्रा**

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करें कि क्या भारत में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी. ट.	0	10156	10491	8498
अन्य देश	मी. ट.	105	898	773	2435
कुल आयात	मी. ट.	105	11054	11264	10933
कुल में चीन के आयातों का आयातों %	%	0%	92%	93%	78%

58. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में गिरावट हुई है जांच की अवधि के दौरान

**ख. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव**

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस बात का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में तमाम उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है। अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का न्यूनीकरण अथवा कीमत वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

**क. कीमत में कटौती**

60. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत सहित आयातों के पहुंच की कीमत से तुलना नीचे दिए गए अनुसार की है :
60. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत सहित आयातों के पहुंच की कीमत से तुलना नीचे दिए गए अनुसार की है :

कीमत में कटौती	यू ओ एम	चीन
आयात की मात्रा	मी. ट.	8498
पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	71788
निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	****
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	****
कीमत में कटौती	%	****
कीमत में कटौती	रेंज	0-10

उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन से कीमत में सकल स्तर पर कटौती मामूली है।

**ख. कम कीमत पर बिक्री**

61. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण उन्हें हो रही कम कीमत पर बिक्री के कारण हानि की भी जांच की है।

कीमत में कटौती	यू ओ एम	चीन
आयात की मात्रा	मी. ट.	8498
पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	71788
क्षति रहित कीमत	रु./ मी. ट.	****
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	****
कीमत में कटौती	%	****
कीमत में कटौती	रेंज	5-15

62. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री से हानि हुई है।

**ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

63. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास हो रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से समान अवधि में हुई होती, याचिकाकर्ता ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के संबंध में ब्यौरे दिए हैं :

कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.		89503	72817	71788
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100	81	80
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	75	73
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	72	74

64. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। जांच की अवधि के दौरान कीमत में न्यूनीकरण और ह्रास हुआ है।
65. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों की घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन मात्रा; नकदी के प्रभाव, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों का एक वस्तुपरक और पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।



66. घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मानदण्डों की चर्चा यहां नीचे की गई है :

i. **बाजार हिस्सा** : घरेलू उद्योग के आयातों, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2013- 14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
<b>मांग</b>					
चीन से आयात	मी. ट.	0	10156	10491	8498
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	105	898	773	2435
केप्टिव के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	450805	550008	538075	536140
अन्य उत्पादक की बिक्री	मी. ट.	547682	498119	496256	594166
कुल मांग	मी. ट.	998593	1059181	1045595	1141239
<b>मांग में बाजार हिस्सा</b>					
चीन	%	0%	0.96%	1.00%	0.74%
अन्य देश	%	0%	0.08%	0.07%	0.21%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	45%	51.93%	51.46%	46.98%
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	55%	47.03%	47.46%	52.06%

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, जहां तक मांग की तुलना में संबद्ध देश के बाजार हिस्से का प्रश्न है, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात मामूली हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोध में दर्शायी गयी भारत में मांग (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है) समर्थकों सहित अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा केप्टिव उत्पादन के आंकड़ों को शामिल नहीं करता है। इस कारण से भारतीय उद्योग द्वारा अपने याचिका में यथा दर्शाये गये भारत में मांग पूरा होने से कम होता है।

ii. **लाभप्रदता और निवेश पर आय** : यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की हानि पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कम हो गयी। लाभप्रदता के संबंध में अन्य संकेतक सुधार को दर्शाते हैं।

विवरण		2013- 14	2014- 15	2015- 16	जांच की अवधि
लाभ एवं हानि	रु / .मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-71	-140	-44
लाभ एवं हानि	रु .लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-86	-163	-54
अवमूल्य	रु .लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	182	144	108

नकद लाभ	रु .लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	21	-184	6
नियोजित पूंजी	रु .लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-123	-81	-83
नियोजित पूंजी पर आय	%	****	****	****	****
नियोजित पूंजी पर आय	सूचीबद्ध	-100	-68	-215	-45

- iii. **उत्पादन और क्षमता का उपयोग :** यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच की अवधि में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग में अपनी एक निर्माण सुविधा को बंद कर दिया है और अन्य दो संयंत्रों में उत्पादन रोक दिया है। इस कारण से घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति के अवधि के दौरान कमी हुई है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कमोवेश वही रहा है।

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	811000	763000	690000	690000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	85	85
उत्पादन	मी. ट.	585354	701750	633262	641710
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	108	110
क्षमता उपयोग	%	72.18%	91.97%	91.78%	93.00%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	127	129

- iv. **बिक्री की मात्रा:** घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है और घरेलू बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कमी के कारण गिरावट दर्शायी है। बिक्री की मात्रा और बिक्री के मूल्य का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू बिक्री मात्रा	मी. ट.	450805	550008	538075	536140
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	119	119
घरेलू बिक्री मूल्य	रु./ मी. ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	72	74

- v. **माल भंडार :** संबद्ध वस्तुओं के माल भंडार के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की
-------	------	---------	---------	---------	---------

					अवधि
औसत भंडार	मी. ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	98	100
बिक्री का %	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	98	100

उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का औसत भंडार क्षति की अवधि के दौरान कमोवेश वही रहा है।

vi. **रोजगार और मजदूरी** : रोजगार और मजदूरी के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	105	103
वेतन	रु. लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	131	132
प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष मजदूरी	रु.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	125	128

उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि के दौरान कमोवेश वही रही है। हालांकि, उसी अवधि के दौरान उनकी मजदूरी में वृद्धि हुई।

vii. **उत्पादकता**: नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादन के मामले में उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन (मी. ट.)	मी. ट.	585354	701750	633262	641710
कर्मचारी	सं..	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	105	103
उत्पादन/ कर्मचारी	मी. ट./ सं.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	103	106

उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में क्षति के इन सभी वर्षों की अवधि में सतत रूप से वृद्धि हुई है।

- viii. **पाटन का आकार :** पाटन का आकार उस सीमा का एक संकेतक है जिस सीमा तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।
- ix. **पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता :** घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग की बहुत प्रतिस्पर्धी दरों पर वैश्विक वित्तीय बाजार से दीर्घाविधि संसाधन जुटाने की क्षमता है।
- x. **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक :** यह जांच दर्शाती है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी मांग है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम है।
- xi. **वृद्धि :** जैसा कि पैरा 66(ii) में तालिका से देखा जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि नकद लाभ आधार वर्ष में (11,959) लाख रुपए से जांच की अवधि में 754 लाख रुपए हो गया है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने वृद्धि से संबंधित मानदण्डों के संबंध में सुधार दर्शाया है।

#### ग. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

67. वास्तविक क्षति की मौजूदगी की जांच करने के बाद, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों, कम कीमत पर इसकी बिक्री और कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के प्रभावों, पाटनरोधी संबंधी करार और भारतीय नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक कारणों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच किया गया है कि क्या पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकता था।

#### तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

68. जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात अधिक मात्रा में नहीं हुआ है। इस कारण से अन्य देशों से आयातों पर इस अर्थ में विचार नहीं किया जा सकता है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है। साथ ही, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त हैं परंतु घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान सतत घाटे दर्शाये हैं।

#### मांग में संकुचन और शपथ के पैटर्न में परिवर्तन

69. क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में सतत वृद्धि हुई है। इस कारण से मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

#### प्रौद्योगिकी में विकास

70. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला एक कारक नहीं है।

#### विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

71. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसमें घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में भूमिका निभा सकता था क्योंकि कच्चे माल और संबद्ध वस्तु का आयात इस देश में स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है।

#### घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

72. प्राधिकारी द्वारा क्षति का विश्लेषण केवल उनके घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस कारण से निर्यात बाजार में कार्य निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण पर प्रभाव नहीं डाला है।

**घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

73. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन के मामले में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
74. इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती थी।

**घ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना****घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

75. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. संबद्ध देश के निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं का भारी उत्पादन और अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इसके अलावा, इस प्रकार के निर्यातकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता अपने आप में घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से कई गुणा अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पी सी आई वूड मेकेंजी के लिए गए उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त क्षमता का उल्लेख नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

चीन में क्षमता	27970000
अनुमानित निर्यात योग्य क्षमता	9110000
घरेलू उद्योग की क्षमता	690000
अनुमानित भारतीय उत्पादन	2235632
घरेलू उद्योग का उत्पादन	641710
घरेलू उत्पादकों की बिक्री	1130306
घरेलू उद्योग की बिक्री	536140
भारत में कुल घरेलू उत्पादन के % के रूप में क्षमता	1251%
सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री के % के रूप में चीन में क्षमता	2475%
कुल घरेलू उत्पादन के % के रूप में निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता	407%
सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री के % के रूप में निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता	806%

हाल में टर्की ने चीन से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि चीन के निर्यातक न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी पाटन प्रथाओं में लिप्त हैं।

- ii. यह तथ्य कि चीन के निर्यातक पाटन प्रथाओं में लिप्त होना जारी रखे हुए हैं, भारत में उनकी वर्तमान कीमतों से सिद्ध हो गया है। इसके अलावा, यह तथ्य कि वे अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में पाटन में लिप्त होना जारी रखे हुए हैं, इस तथ्य से सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्कों को अन्य देशों द्वारा चीन के आयातों पर लगाया गया है।
- iii. चीन के निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग इस सूचना को प्राप्त नहीं कर पाए थे जो चीन के निर्यातकों के निर्यात उन्मुखीकरण को सिद्ध करता हो। सी सी एफ समूह की वेबसाइट से

लिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निर्यात की मात्रा 2013 – 2018 के बीच दुगुनी हो गई है। चीन के अन्य निर्यातकों के आंकड़ों की जांच भी उसी प्रवृत्ति को दर्शायेगी। हालांकि, इसी कारण से चीन के निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया।

- iv. यह सच है कि चीन संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन का लगभग 75-80 प्रतिशत पर कब्जा किए हुए हैं। इस प्रकार की अत्यधिक क्षमता/ उत्पादन उन्हें भारत सहित विश्व के अन्य बाजारों को असंतुलित करने की अनुमति देता है।
- v. पिछले पांच वर्षों में पूरे विश्व में बढ़ायी गयी क्षमताओं की लगभग 90 प्रतिशत क्षमता चीन में बनी है। चीन में मांग में गिरावट के साथ साथ इस प्रकार के विस्तार ने अन्य देशों के लिए और अधिक खतरा पैदा किया है।
- vi. इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं का कुल उत्पादन अपने आप में भारतीय उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत तक चीन में घरेलू मांग से अधिक है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को जारी नहीं रखे जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने और परिणामी क्षति के होने की संभावना के लिए स्पष्ट है।
- vii. भारतीय बाजार चीन के निर्यातकों के लिए आकर्षक हैं क्योंकि भारत चीन से बाहर सबसे बड़ा बाजार जो शेष विश्व के बाजार का 30 प्रतिशत से अधिक है।
- viii. वर्तमान पाटन और क्षति का मौजूद होना अपने आप यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को उस स्थिति में बहुत अधिक क्षति होना तय है जब वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को रद्द कर दिया जायेगा।

#### **उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

76. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
  - i. केवल क्षमता होना क्षति की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवेदक के लिए यह प्रमाणित करता भी अपेक्षित है कि इन निर्यातकों के पास इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता होने के फलस्वरूप भारत में उत्पादों का पाटन होगा। हालांकि, आवेदक इस प्रकार के किसी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए और इस कारण से इस प्रकार का आरोप संभावना के मानदण्ड के अंतर्गत वैध साक्ष्य नहीं होता है।
  - ii. वर्तमान मामले में विश्लेषण भारतीय बाजार में प्रवेश करने की उनकी संभावना को देखते हुए चीन में मौजूदा क्षमताओं की संभावना का एक विस्तृत विश्लेषण के बिना पूर्ण नहीं होगा।
77. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क की जांच की है।

#### **वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर**

78. यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है लेकिन संबद्ध देश से आयातों की मात्रा मूल और वर्तमान दोनों जांचों में बहुत कम है।

#### **जांच की अवधि के बाद के दौरान आयातों की मात्रा**

79. डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात जांच के बाद की अवधि के दौरान भी भारत में मांग की तुलना में बहुत कम रही है।

देश	जांच की अवधि के दौरान आयात (मी. ट.)	जांच की अवधि के बाद आयात (मी. ट.)
चीन	8498	10407 (वार्षिक)

**भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता**

80. वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात संबद्ध देश द्वारा भारत में किया जा रहा है, कमोवेश वही है यदि उसकी तुलना उन कीमतों से की जाये जिस कीमत पर संबद्ध देश अन्य देशों को निर्यात कर रहा है जो यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार कमोवेश उसी स्तर पर है जिस स्तर पर अन्य देश हैं। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारतीय बाजार की इस तरह की कोई कीमत आकर्षकता नहीं है।

**संबद्ध देश में भारी मात्रा में उत्पादन क्षमता**

81. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास विशाल क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश में विभिन्न निर्माताओं के पास भारी उत्पादन क्षमताओं का साक्ष्य उपलब्ध कराया है। हालांकि प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि टर्की और मिस्र जैसे अन्य देश हैं जहां चीन के निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा खप जाता है।

**संबद्ध देश से निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण**

82. याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध देश में निर्यातक प्रमुख रूप से निर्यात उन्मुख होते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में ये निर्यातक संभवतः अपने निर्यात को पाटित कीमतों पर भारत में भेजेंगे। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देश के पास विशाल अतिरिक्त क्षमता है जो संबद्ध देश में घरेलू मांग के अनुपात में नहीं है। इस कारण से निर्यातक अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए निर्यातों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, यह तथ्य की पी ओ वाई के कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक प्रयोक्ताओं ने पहले ही चीन से निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है, घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि करते हैं। हालांकि, प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि चीन के निर्यातों का कोई निर्यात उन्मुखीकरण नहीं है क्योंकि यह जांच की अवधि के दौरान 91,10,000 मी. ट. तक की अपनी अप्रयुक्त क्षमता में से केवल 3,57,808 मी. ट. का निर्यात करता है।

**इस उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता और भारतीय बाजार के मामले में घरेलू उद्योग का जोखिम**

83. भारतीय बाजार बहुत अधिक कीमत संवेदनशीलता है। उपभोक्ता कीमत पर सबसे अधिक विचार करते हुए अपनी खरीद के बारे में निर्णय लेते हैं।
84. यहां यह नोट करना संगत है कि किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग के प्रमुख तर्कों जिनका खंडन अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है, का विधिवत समाधान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।

**घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात किया गया अनुरोध**

85. यह कि वर्तमान पाटन और क्षति की मौजूदगी पूरे विश्व में शुल्कों को सतत रूप से लगाने के लिए एक ठोस कारक है। यह भी अनुरोध किया गया है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के वर्तमान उच्च स्तर चीन के उत्पादकों और निर्यातकों की स्वीकार्य रूप में निर्यात उन्मुख प्रकृति से भारतीय उद्योग को सतत संरक्षण देने की आवश्यकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।
86. यह कि प्राधिकारी द्वारा कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण जैसे क्षति मानदण्डों के संबंध में किया गया विश्लेषण स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।
87. प्राधिकारी की इस टिप्पणी के संबंध में कि “चीन से कीमत में कटौती सकल योग्य के स्तर पर बहुत मामूली है”, यह अनुरोध किया जाता है कि कीमत में कटौती पर विचार अलग से नहीं किया जा सकता है और इस पर विचार हमेशा कम कीमत पर बिक्री और कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास के साथ साथ किया जाता है। चूंकि, संबद्ध वस्तुओं से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है/ उसमें ह्रास हो रहा है, अतः कम कीमत पर बिक्री और आयातों के दबावकारी/ ह्रासकारी प्रभाव के संदर्भ के बिना कीमत में कटौती पर विचार करना पूर्ण रूप से अनुपयुक्त होगा।

88. यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक नहीं हो सकता है कि किसी भी निर्यातक ने इन जांचों में सहयोग नहीं किया है। निर्यातकों से लेन देन वार विस्तृत आंकड़ों के अभाव में, सकल योग के स्तर पर कीमत में कटौती का विश्लेषण बहुत अधिक सीमा तक अपने महत्व को खो देता है। यदि निर्यातकों को प्राधिकारी से उनके द्वारा सहयोग न किए जाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, तब यह न्याय का मजाक होगा।
89. आयातों में गिरावट के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि चीन के निर्यातकों ने आयात में इस गिरावट को प्राधिकारी को यह विश्वास करने के लिए भ्रमित करने हेतु दक्षतापूर्वक किया है।
90. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट संपूर्ण रूप में कंपनी के कार्य निष्पादन और आशाओं के लिए है जबकि वर्तमान जांच केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं के संदर्भ में पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता इन शुल्कों को जारी न रखे जाने की स्थिति में गंभीर रूप से समाप्त हो जायेगी। इस कारण से शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में पी ओ वाई क्षेत्र इस आधार को नुकसान पहुंचायेगा।
91. चीन के उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षकता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन के निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर संभावना से संबंधित सूचना के उपलब्ध नहीं होने को घरेलू उद्योग के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि चीन के उत्पादकों ने बहुत रणनीतिक तौर पर वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया था क्योंकि उनके आंकड़े यह सिद्ध करते कि वे निर्यात पर निर्भर हैं और भारतीय बाजार तथा अन्य बाजारों में भारी मात्रा में पाटन कर रहे हैं।
92. कुछ आयातकों का यह तर्क की इस मामले में शुल्कों को सतत रूप से लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अग्रिम अधिकरण के अंतर्गत हो रहा है, यह कहना सही नहीं होगा कि शुल्कों को सतत रूप से लगाने के कारण जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
93. यह कि चीन के निर्यातकों को उनके द्वारा सहयोग न किए जाने के लिए सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए और निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता के संबंध में आंकड़ों के न होने पर शुल्कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण से घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन के निर्यातकों के असहयोग को उन्हें अनुचित और अनावश्यक लाभ के एक साधन के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
94. यह तथ्य कि भारत और अन्य देशों में चीन के निर्यात की कीमतें तुलनीय हैं, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि शुल्कों को हटाये जाने की स्थिति में, चीन से आयात केवल इन कीमतों पर होगा और भारत में पी ओ वाई उद्योग की स्थिति निश्चित रूप से और बदतर हो जायेगी।
95. यह कि बहुत अधिक मात्रा में वर्तमान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन है। अतः क्षति और पाटन की संभावना बिल्कुल निकट है और इस कारण से वर्तमान जांच शुल्कों को सतत रूप से लगाने के लिए उपयुक्त है। उसके द्वारा प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क को सतत रूप से लगाने की पुष्टि करें।

#### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण में किया गया अनुरोध**

96. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के बीच आयात संबंधी आंकड़ों को अलग अलग करने की पद्धति उपलब्ध कराने में असफल हो गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में आयात संबंधी आंकड़ों को अलग करके उपलब्ध कराना चाहिए।
97. आवेदक का कुल उत्पादन में केवल 28 प्रतिशत हिस्सा होता है और इस प्रकार के लघु हिस्से के आधार पर संभावना का कोई विश्लेषण सही परिणाम नहीं देगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि हाल के एक अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने केवल इस कारण से इस जांच को समाप्त कर दिया है कि आवेदक का भारत में कुल उत्पादन में केवल 27 प्रतिशत हिस्सा है।



98. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय हालत संपूर्ण रूप में भारतीय घरेलू उत्पादकों की अपेक्षाकृत व्यापक औद्योगिक हालत को नहीं दर्शाता है। इस कारण से उन्होंने इस जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया अथवा वैकल्पिक रूप में घरेलू उद्योग को भारत में पी ओ वाई के उत्पादकों के अपेक्षाकृत व्यापक खंड को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए।
99. प्राधिकारी अन्य उत्पादों जैसे टेक्सचराज्ड यार्न पर पी ओ वाई के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन नहीं किया है। इस संबंध में प्राधिकारी की सबसे सरल टिप्पणी यह है कि यह केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और इसमें अन्य उत्पादों और उद्योगों के प्रभाव को स्वीकार्य नहीं किया गया है।
100. प्राधिकारी को इसके द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किए जाने में अपनाई गई तर्क और पद्धति को रिकार्ड करना है। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सिम्पलीसिटर से आगे इस पद्धति को शामिल करें।
101. चीन से किया गया आयात भारत में उत्पादन और मांग की तुलना में नगण्य है और इस कारण से चीन से आयात को घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
102. अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ साथ घरेलू उद्योग का मांग में 99 प्रतिशत हिस्सा होता है और चीन से किए गए आयात केवल 1 प्रतिशत हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।
103. प्रतिवादी इस तथ्य को दोहराते हैं कि पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है और यह किसी उत्पादक अथवा निर्यातक के वास्तविक आंकड़ों को नहीं दर्शाता है और इस कारण से यह किसी भी रूप में क्षति के आकलन का आधार नहीं बन सकता है।
104. अत्यधिक क्षमताएं घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने अथवा उसके जारी रहने की संभावना का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी को इस बात की जांच करने के लिए अपने आकलन को अवश्य पूरा करना चाहिए कि क्या कोई अतिरिक्त क्षमता है, जिसके फलस्वरूप विशेष रूप से भारत में आयातों का पाटन हो सकता है।
105. घरेलू उद्योग सभी आर्थिक मानदण्डों जैसे उत्पादन, क्षति के उपयोग के संबंध निष्पादन सही रूप में हो रहा है और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने भी बढ़े हुए उत्पादन के बावजूद उसी स्तर पर अपने माल भंडार को कायम रखा है।
106. भारतीय बाजार की कीमत की कोई आकर्षकता नहीं है क्योंकि भारत और तीसरे देशों में चीन के निर्यातों की कीमत तुलनीय होती हैं। अतः इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन के उत्पादों के लिए मांग से अधिक कथित उत्पादन क्षमताएं हैं अथवा यह कि निर्यात उन्मुखीकरण से भारत में बहुत अधिक मात्रा में आपूर्ति की स्थिति बनी है।
107. कोई सतत क्षति नहीं हो रही है और न ही वर्तमान मामले के तथ्यों और स्थितियों के आलोक में पाटन अथवा क्षति के फिर से होने की कोई संभावना है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध को बार बार दोहराया गया है और इसका समाधान पूर्व में प्रकटन विवरण में किया गया था। उपर्युक्त जांच परिणाम में घरेलू उद्योग सहित इन हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे सभी तर्कों पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने नीचे संगत पाई गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों के उन अनुरोधों की जांच की है, जिनका समाधान अन्य स्थानों पर नहीं किया गया है।

क. आयात संबंधी आंकड़ों को अलग करने के बारे में किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने क्षति की अवधि और जांच के बाद की अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस से आयात संबंधी आंकड़ों की मांग की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के विवरण के आधार पर आयात संबंधी आंकड़ों को अलग अलग किया था।

- ख. कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को एक साथ देखे जाने के बाद यह नोट किया जाता है कि चीन से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होने के बावजूद (क्योंकि आयात भारत में अग्रिम अधिकरण के अंतर्गत हो रहा है), घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य निष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ। चूंकि, हुई वर्तमान हानि अथवा क्षति का कारण संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात नहीं हो सकता है। अतः घरेलू उद्योग को क्षति होने की उनकी संभावना की संभाव्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है।
- ग. घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों के संबंध में की चीन के निर्यातकों के असहयोग को उनके विरुद्ध माना जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि वास्तव में प्राधिकारी ने प्रथम निर्णायक समीक्षा में किसी निर्यातक द्वारा भाग न लिए जाने के बावजूद पाटन और क्षति की संभावना को पाने के बाद इन शुल्कों के लिए समय विस्तार दिया था। इसके अलावा, विश्व की ओर चीन के निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण को नगण्य पाया गया है क्योंकि चीन ने जांच की अवधि के दौरान 91,10,000 मी. ट. तक की अपनी उपयोग न की गई क्षमता में से केवल 3,57,808 मी. ट. का निर्यात किया था। इसके अलावा, चीन के निर्यात का विश्लेषण यह दर्शाता है कि टर्की और मिस्र (चीन पर पाटनरोधी शुल्क टर्की द्वारा लगाये जाने के बाद भी) जैसे देशों में विश्व को संबद्ध वस्तुओं का चीन द्वारा बहुत कम मात्रा में किया गया निर्यात खप जाता है। इस कारण से इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अन्य निर्यात बाजार चीन के अतिरिक्त निर्यात यदि कोई हो, को खपाने के लिए उपलब्ध है।
- घ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संबंध में किए गए अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि वह कीमत जिस पर भारत में संबद्ध देश द्वारा संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, उनकी कीमतों से तुलना किए जाने पर कमोवेश एक जैसी हैं जिस पर संबद्ध देश अन्य देशों को निर्यात कर रहा है जो यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार कमोवेश उसी स्तर पर है जिस स्तर पर अन्य देश हैं। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारतीय बाजार की इस प्रकार की कोई कीमत आकर्षकता नहीं है।

### **निष्कर्ष**

109. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष नीचे दिए गए अनुसार है :
- घरेलू उद्योग को इस अवधि के दौरान भी लगातार क्षति उठानी पड़ी जब संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ था अथवा मामूली आयात हुआ था। इस कारण से, इस क्षति का कारण पाटित आयात नहीं हो सकता है।
  - घरेलू उद्योग भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और चीन के निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण को न्यायोचित ठहराने के लिए सक्षम नहीं था।
  - रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह नहीं दर्शाते हैं कि चीन से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
  - घरेलू उद्योग लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में अपने दावे की पुष्टि करने में असफल रहा।

### **सिफारिशें**

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, हानि और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये थे। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, हानि और कारणात्मक संबंधों की जांच शुरू करने तथा उसे आयोजित करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटन और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति उस

स्थिति में होने की संभावना है जब वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को ऊपर में दिए गए कारणों से और आगे न बढ़ाया जाये, और न ही पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। इस कारण से प्राधिकारी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2018

**Final Findings**

Subject: Sunset Review investigation on imports of Partially Oriented Yarn (POY), originating in or exported from China PR.

- F. No.—7/01/2017-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Partially Oriented Yarn (POY), (hereinafter also referred to as subject goods / product under consideration / PUC) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as subject Country). The final findings notification of the Authority was published vide notification 14/10/2005- DGAD dated 8th June, 2007. On the basis of the findings, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 92/2007 dated 03.08.2007.
2. Subsequently, the Authority initiated a sunset review of the above anti-dumping duty vide notification dated 11th February, 2011 and recommended continued imposition of definitive Anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the above country vide Final Finding Notification No. 15/27/2010-DGAD dated 10th February, 2012. The duties were extended vide Customs Notification No. 22/2012-Customs (ADD) dated 2nd May 2012 for a further period of 5 years i.e., until 1st May 2017.
  3. WHEREAS in terms of Section 9A (5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
  4. Whereas, a petition has been filed by M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as “petitioner or applicant”) in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a Sunset Review of the Anti-dumping duty in force on import of Partially Oriented Yarn (POY) for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the above goods originating in or exported from China.
  5. And whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 7/01/2017-DGAD dated 28<sup>th</sup> April, 2017, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the above Rule to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
  6. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

**PROCEDURE**

7. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
- i. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of the Sunset Review of anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
  - ii. The Authority issued a public notice dated 28<sup>th</sup> April, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating Sunset Review investigation concerning imports of the subject goods.
  - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from subject country and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - iv. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
    1. Chemical Fibres Association
    2. Cixi Santai Chemical Fibre Co. Ltd.
    3. Zhejiang Cifu Chemical Fiber Co. Ltd
    4. W.W. Textile Co.,Ltd
    5. Hangzhou Huaxin Textile Co. Ltd.
    6. Xinxiang Sunshining Textiles Co. Ltd.
    7. Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fibre Co. Ltd.
    8. Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co. Ltd.
  - v. However, none of the producers/exporters subject country has filed their Questionnaire responses in the above matter.
  - vi. The Authority also forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
    1. Suntex India
    2. Galaxy Textiles
    3. Harmony Yarns Pvt. Ltd.
    4. AVM Exports
    5. Garg Tex-O-Fab Ltd.
    6. Boghara Polyfab Private Limited
    7. Silvassa Industries Ltd.
    8. Beekaylon Synthetics Ltd.
    9. Alok Industries Ltd.
    10. Bajari Filaments P. Ltd.
    11. Sidhvan Yarns Ltd.
    12. Crimpon Yarns
    13. Uni Tex Texturisersz
    14. Unify Texturisers

15. Ghoomtex (India) Pvt. Ltd
  16. Mehratex India P. Ltd
  17. SRV Polytex Pvt. Ltd.
  18. Synfab Sales & Industries Limited
- vii. The following importers/users/user associations have filed their Questionnaire responses / submissions in the above matter:
    1. All India Texturisers' Association
    2. Bhumi Yarns Pvt. Ltd.
    3. Unify Texturisers Pvt. Ltd.
    4. Shekhawati Poly Yarn Limited
  - viii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
  - ix. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.
  - x. The period of investigation was proposed as January 2016 to December 2016 (12 months) by the petitioner. However, the Authority considered it more appropriate to carry out the investigation taking into account the period of investigation as April 1, 2016 to March 31, 2017 (12 months). For the purpose of analyzing injury data, the data of previous three previous years, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI will be considered.
  - xi. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
  - xii. Non-injurious price has been determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
  - xiii. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
  - xiv. The Authority held an oral hearing on 22<sup>nd</sup> February, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties.
  - xv. All the parties who presented their views in the Oral Hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders thereafter.
  - xvi. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
  - xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
  - xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
  - xix. \*\*\*in this Disclosure Statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

- xx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is

1US\$ = Rs.67.95

### **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

#### **Submissions by the Domestic Industries**

8. The submissions made by domestic industry are as follows:
- The Product under consideration is Partially Oriented Yarn, generally known as POY. It is the yarn of Polyester and is an intermediate, which is subject to further processing, for example, texturising or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics. It falls under the Customs Tariff Heading 5402.4600 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items.
  - The imported product is also imported under other headings apart from the heading expressly provided. In any case, as per the practice adopted by the Authority, the custom heading is indicative only and is in no way binding upon the scope of the Product under Consideration.
  - The present investigation being a Sunset Review, the scope of the Product under Consideration cannot be changed from what it was in the original investigation.

#### **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

9. None of the interested parties have submitted any comments/submission with respect to the Product under Consideration.

#### **Examination by the Authority**

- The Product under consideration is Partially Oriented Yarn, generally known as POY. It is the yarn of Polyester and is an intermediate, which is subject to further processing, for example, texturising or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics.
- The product under consideration is classified under chapter heading 54024600. However, the subject goods are also being imported under other tariff headings. Further, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- Present investigation, being a Sunset Review of the duty in force, the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.
- With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:-

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
- After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of physical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing. The two are technically and commercially substitutable.
- The Authority holds that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules;

### **SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

#### **Submissions by the Domestic Industry**

16. The submissions made by the domestic industry are as follows:
- The Sunset Review petition has been filed by M/s. Reliance Industries Limited and has been duly supported by M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd, M/s. JBF Industries Limited, M/s. Garden Silk Mills Ltd, and M/s. Alok Industries Limited.

- ii. The petitioner and the supporters account for a major proportion of the domestic production of the subject goods. Even though Rule 5 is not applicable to Sunset Review investigations, the applicant and the supporters together appropriately reflect the state of the Domestic Industry.
- iii. Petitioner has not imported the subject goods from subject country during the POI. Petitioner is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus the petitioner is eligible domestic industry under Rules 2(b) and 5(3) of the AD Rules.

**Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

17. None of the interested parties have submitted any comments/submission with respect to the scope of domestic industry and its standing.

**Examination by the Authority**

18. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

*“(b)“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

19. The application in the present case has been filed by M/s Reliance Industries Limited and has been supported by M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd, M/s JBF Industries Limited, M/s Garden Silk Mills Ltd, and M/s Alok Industries Limited.
20. It may be noted that the petitioner along with the supporters constitute major proportion of the domestic production of the subject goods. The authority determined at the stage of initiation that the petitioner along with the supporters, being the major producer of the subject good satisfied requirement of standing under the Rules and the Petitioner constituted domestic industry within the meaning of the Rules. Accordingly, the Authority holds that that the petitioner satisfied the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

**ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

**Submissions by the Domestic Industry**

21. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
- ii. The petitioner has provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
- iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in indexed version as the information is business proprietary information.

**Submission made by the producers/exporters/other interested parties**

22. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to demand. In the absence of such data, a proper volume effect analysis cannot be undertaken.
- ii. The domestic industry has claimed and has been allowed excessive confidentiality in the sense that they have not made available their annual report in the public file.
- iii. Domestic Industry has also not provided sufficient details of their costing.

**Examination by the Authority**

23. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

24. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

*“Confidential information”*

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

25. The WTO Agreement on Anti-Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information-

*“Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.*

*Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.*

*Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.*

*Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti-Dumping) provides as follows:- Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.”*

26. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

**OTHER MISCELLENEOUS ISSUES****Submissions by the Domestic Industry**

27. As regards the legal validity of the extension of duties after the expiry of the period of five years, it is submitted that the responding parties need to appreciate that the anti-dumping duties are imposed by the Central Government i.e., the Ministry of Finance in this case. If at all they have any issue, legal or otherwise, with regard to the legal validity of the extension of duties, they ought to have approached the appropriate forum. This issue cannot be



raised during the Sunset Review investigation. It is pertinent to note that the case law relied upon by interested parties is in the context of second proviso to Section 9A(5) and not for interpretation of first proviso to Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975."

28. The interested parties have argued that the duties should not be extended beyond 10 years period. They have relied on the findings of the Authority in the case of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR. However, a mere reading of the said paragraph clearly establishes that the reliance of the interested parties in this regard is misplaced. The above observation of the Authority is to ensure that duties are not stretched beyond what is required. There is nothing in the law to suggest that there ought to be some kind of cap on the number of years for which the anti-dumping duty protection can or should be given to any industry. The provisions of Section 9A(5) are absolutely clear on this issue. It is a matter of fact that the anti-dumping duties have continued for more than 10 years in a host of cases in India. In the present case, the fact that there is the presence of current dumping and injury establishes that the revocation of the duties would be disastrous for the domestic manufacturers of the subject goods including the petitioner.
29. The interested parties have claimed that the POY manufacturers including the petitioner make high profits on sales of POY while selling PTY, which is a downstream product, at unremunerative and low prices with little margin. In this regard, the Domestic Industry submitted that the above claim of the interested parties is completely baseless and far from reality. The Authority has already conducted domestic verification in the present case and it has already demonstrated that the domestic POY manufacturers including the petitioner are selling the subject goods on non-remunerative prices. In the circumstances, it is absolutely incorrect to claim that the domestic manufacturers make high profits on sales of POY.
30. The Domestic Industry also submitted that the claims of interested parties regarding artificially low prices of PTY are also completely baseless. It is a matter of fact that the sales of PTY are profitable after taking into account the conversion cost. The responding parties have not been able to appreciate the fact that the petitioner as well as the supporters, being integrated producers, have certain advantages with regard to the PTY business. This is reflected from the fact that the integrated producers have seen a significant growth as compared to the stand-alone producers solely on account of the inherent efficiencies of integrated producers. It is also pertinent to mention that in last few years texturizing units have also grown their capacities. Further, the respondents have not revealed the other factors which may be contributing to their poor performance in terms of the higher electricity costs, taxation issues etc. Therefore, the claims of the interested parties in this regard are completely baseless.
31. As regards the claims that the raw material for manufacturing PTY/polyester fabrics suffer from anti-dumping duties, it is submitted that the claim of the respondents is not correct. There is no anti-dumping duty on MEG and Fully Drawn Yarn required for manufacturing polyester fabrics. Further, there is no anti-dumping duty even on PTA imported from sources other than a few. According to the Domestic Industry, the respondents have not revealed to the Authority that the production of fabrics was affected due to cheaper and dumped fabrics coming from China and not because of any incidence of anti-dumping duties on the raw materials. Taking cognizance of this fact, the Government enhanced the custom duty on fabrics from 10% to 20% effective from October 2017.
32. It is also factually wrong that export of fabrics was restricted due to ADD on POY. First of all, any imports of raw material meant for production of export goods are exempt or not leviable to anti-dumping duties under various schemes of the Government of India. Secondly, the domestic users as well as the exporters of the finished products are free to import POY from a host of other sources which are not subject to anti-dumping duties. It may also be noted that as per SRTEPC (Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council), Government of India, the exports of fabrics have grown by 3% as compared to last year. Further the exports of PTY grew by about 34% between 2014-15 and 2016-17. Therefore, it is clear that the apprehensions made by the respondents are not factually correct and ought to be rejected outright.

#### **Views of the opposing interested parties**

33. The Anti-Dumping duties imposed in the present case expired on 1 May, 2017 and the Ministry of Finance Notification No. 16/2017-Customs (ADD) extending the duty for the interim of the SSR was issued only on 9 May, 2017. It is established law that where a specified time period pursuant to a customs notification is required to be extended, then the same must be done on or before the expiry of the original term in order to maintain continuity. In the present case, there was no extension notification of anti-dumping duty before the expiry of the parent

notification for imposition of anti-dumping duty. Therefore, the duty has ceased to exist due to efflux of time. In light of the above ruling, the extension of anti-dumping duty in the present case is illegal.

34. In the present review, the original investigation was initiated in December, 2005 and duty was levied in June, 2007. Thus, the subject goods have been subject to anti-dumping duty for over 10 years. The essential facts of the present case do not disclose any special circumstances warranting continuation of anti-dumping duty. This principle emerges from the Authority's final findings dated 20 May 2013 in the Sunset-Review of Anti-dumping on imports of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR case where the Authority has held that:

*"It is the endeavor of the Authority not to continue the duty beyond a period of 10 years except in special cases where the authority feels that anti-dumping duty is absolutely necessary depending upon the facts and circumstances of the individual cases"*

35. The domestic industry has received adequate protection from DGAD since the imposition of duty in the original investigation. The protection was increased further by continuation of duty in the last sunset review investigation. We note that at the conclusion of the first sunset review itself, the Authority had found negative injury margin. As such, the negative economic parameters of the domestic industry, which had warranted the original imposition, had already ceased to exist five years ago itself. Despite such facts, the Authority had recommended the continuation of duties. However, in the present case, the continued lack of injury is evidenced in the Petitioner's performance parameters and hence, the Respondents request that the antidumping duty should not be extended any further.
36. Partially Oriented Yarn (POY) is a raw material for manufacturing Polyester Textured Yarn (PTY), which is a fully drawn, fully oriented polyester mono or multifilament yarn with soft crimp, high bulk and texture with cotton feel and very high durability and retention properties. This is manufactured by texturizing POY using high speed texturizing machines. There are many POY manufacturers, like the Petitioner, who have set up facilities for manufacture of the downstream PTY. These producers make high profits on sales of POY while selling PTY at unremunerative and low prices with little margin. In fact, the price difference between the POY and PTY of such producers do not cover the cost of manufacturing involved in texturizing POY. Thus, the individual texturisers are unable to survive in the market and have declined in market share holding from more than 75% to less than 25%.
37. The ADD benefits only a select few businesses such as that of the Petitioner who claim to be the most efficient and control the entire raw material chain. However, the imposition of duties result in damage to the downstream industries which include Texturising / Knitting / Weaving / Processing / Garmenting and all ancillary industries which collectively are the second largest employers in the country and have tremendous scope for further generating employment if this duty is removed. The Purified Terephthalic Acid /Mono Ethylene Glycol /Partially Oriented Yarn /Fully Drawn Yarn—all raw materials required for manufacturing Polyester Fabrics attract 5.5% Custom Duty and anti-dumping duty ranging from 5 cents to 50 cents per Kg which makes manufacturing fabric uncompetitive against the international fabrics which in turn restricts export of fabrics and garments to a great extent.

#### **Examination by the Authority**

38. With regard to the contention of the interested parties that the anti-dumping duties in the present case expired on 1 May 2017 while the extension by the Ministry of Finance on 9 May 2017 therefore the extension of the duties are illegal, the Authority notes that the present Sunset Review investigation was initiated by the Authority before the expiry of the effective duties. In this context, reliance has been placed by interested parties on the case of Kumho Petrochemicals. The Authority has carefully examined the said decision in the backdrop of submissions in this context. A plain reading of the said case goes to show that there was a gap between expiry of duty and extension of duty by Ministry of Finance. Despite such gap, the Sunset Review investigation was not quashed. Designated Authority was allowed to record its final findings which evidently were accepted by Central Government. Clearly, any gap in extension of duties by one year was not held to be fatal to issue of the notification extending duties under the provision of section 9A(5), first proviso. It is further noted that if the interested parties have any issue with regard to the legality of the present notification, this is not the appropriate forum to address that.
39. As regards the contention of the interested parties that the duties cannot be effective beyond 10 year, the Authority notes that it has never been the position of the Designated Authority that duties cannot extend beyond 10 years period. The imposition of duties are to be determined on case to case basis depending upon the facts and circumstances of a particular case.

40. As regards the arguments raised relating to the impact on downstream product, the Authority notes that the subject matter of the present investigation is Partially Oriented Yarn Sunset Review governed by Rule 23. It is important to note that by adopting lesser duty rule and by applying rules of Annexure III while determining Non-Injurious prices, the Authority fully balances any injurious impact on user industry and the applicant industry. Therefore, it would be incorrect to state that Authority has not paid any heed to interests of the user industry. Moreover, the user industry has not been able to establish that the continuation of duties in this case would affect the public interest adversely, as all the imports into India are made under Advance Authorization, as claimed by all interested parties including domestic industry.
41. Regarding the contention of the interested parties that the anti-dumping duties make the exports non-competitive, the Authority notes that there is no merit in such arguments of the interested parties. The imports for the purpose of utilization in an exportable good are free from any anti-dumping duties. Further, the objective of the anti-dumping duties is limited to removing the effect of dumping and to create a level playing field for the domestic manufacturers as well as the exporters. The anti-dumping duties, in no way, restrict the imports but only makes sure that imports do not happen at unreasonable prices. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard are not sustainable.

### **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

#### **Normal Value**

42. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*  
*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **Submissions by the Domestic Industry**

43. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. The Domestic Industry has filed complete information with regard to the normal value and export price which was necessary for the purpose of initiation of an investigation. Further, all the necessary evidence has also been provided in support of claim of normal value as well as export price.
- ii. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

#### **Views of the opposing interested parties**

44. None of the interested parties have offered any comment/submission with regard to normal value.

#### **Examination by the Authority**

45. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice

of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the AD Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers filed any response to the exporters questionnaire issued by the Authority.

46. Accordingly, the normal value and export price for the all the producers/exporters from the subject country have been determined as below:

**Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR**

47. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in subject country and any other market economy third country, the Designated Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of best available information for the like product, with a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the producer/exporters of the subject goods from China PR has been constructed and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**Export price for producers and exporters in China PR**

48. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority has constructed the export price for subject goods on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**DUMPING MARGIN**

49. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing constructed normal value and net export price. The table below shows the so calculated dumping margin for producers/exporters from subject countries.

Sr. No.	Country	Producer/Exporter	Normal Value (Rs./MT)	Net Export Price (Rs./MT)	Dumping Margin (Rs./MT)	Dumping Margin %	Range %
1	China	All exporters/producers	****	****	****	****	30-40

50. It is seen that the dumping margin for the subject goods is more than de-minimus for imports from the subject country.

**METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

**Views of the Domestic Industry**

51. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- Imports of the product under consideration have shown increase over the years. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India;
  - Despite the anti-dumping duties in force, market share of subject country in demand is still increasing. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year;
  - With reduction in the prices by the Chinese producers, the only choice available to the Indian producer is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders and hence the market share;
  - Domestic industry prices, reflect the effect of the prices that are being offered by the importers in the domestic market;
  - The price underselling is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price suppression and depression as they are not able to increase their prices to reasonable level. The main reason for this is low priced imports from China that too at dumped and injurious prices.

- vi. Performance of the domestic industry has remained negative in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.
- vii. The decrease in selling price was more than the decrease in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- viii. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from China. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

**Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties**

52. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority
- i. The Domestic Industry is not suffering any injury and has improved throughout the injury investigation period.
  - ii. The present SSR has been initiated on the basis of the application of the petitioner which holds merely 28 % of the Indian production. In such a case, injury assessment cannot be based on the data of such a miniscule and unrepresentative segments of domestic producers.
  - iii. Capacity of the petitioner as well as its overall production have increased. However, owing to the increased capacity, its capacity utilization decline in the interim of the period of injury. Therefore, there is no evidence of injury based on the petitioner's capacity, production and capacity utilization.
  - iv. Petitioner steadily increased its market share in demand over the period of injury despite decline in total demand.
  - v. There is no price or volume effect from the subject goods from subject country;
  - vi. The Petitioner has admitted that there is no price suppression / depression. The Petitioner has not put forward any claim for price undercutting either. The petitioner has only alleged price underselling.
  - vii. The volume of imports from China PR, in the injury and investigation period is miniscule when compared to the volume of production of the Indian producers and the Indian demand.
  - viii. Rather, considering the data from 2014-15 onwards, there has been a decline in the volume of imports from 10156 MT to 10491 MT in the year 2015-16 and finally to 8523 MT during POI. A projection for increase in imports post-POI will not be the logical conclusion derived out of the above data. Petitioner's claim of injury being caused due to increase in volume of imports in absolute terms is baseless.
  - ix. The Domestic Industry has failed to establish any likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury.

**Examination by the Authority**

53. The impact of the dumped imports on the domestic industry is to be examined in terms of Annexure-II of the AD Rules.
54. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.
55. The Authority proposes to compute the non-injurious price in accordance with Annexure III to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD.
56. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

**A. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS**

**Import Volume**

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Import Volume					
Subject country	MT	0	10156	10491	8498
Other Countries	MT	105	898	773	2435
Total Imports	MT	105	11054	11264	10933
% of imports from China in total imports	%	0%	92%	93%	78%

58. It is noted from the above table that as compared to the previous year there has been a decline in imports of the subject goods from the subject country during POI.

#### **B. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from subject country.

##### **a. Price Undercutting**

60. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net selling price of the domestic industry for subject goods as below:

Price Undercutting	UoM	China
Import Volumes	MT	8498
Landed Value without AD Duty	Rs/MT	71788
Net Selling price	Rs/MT	****
Price Undercutting	Rs/MT	****
Price Undercutting	%	****%
Price Undercutting	Range	0-10

The above analysis shows that the price undercutting from China is insignificant on aggregate level.

##### **b. Price Underselling**

61. The Authority has also examined price underselling suffered by them on account of dumped imports from subject countries as per DGCIS data:

Price Underselling	UoM	China
Import Volumes	MT	8498
Landed Value without AD Duty	Rs/MT	71788
NIP	Rs/MT	****
Price Underselling	Rs/MT	****
Price Underselling	%	***%
Price Underselling	Range	5-15

62. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered price underselling on account of imports of the subject goods from China.

**c. Price Suppression and Depression**

63. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Petitioner has given details regarding the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Price Suppression/Depression	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed Value	Rs/MT		89503	72817	71788
Trend	Indexed		100	81	80
Cost of Sales	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	88	75	73
Net Sales Realization	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	89	72	74

64. From the above Table, it is clear that the landed value of imports from the subject country as well as the Domestic Industry's cost of sales decreased in POI as compared to the previous years. There has been price suppression and depression during the POI.

**Economic Parameters of the Domestic Industry**

65. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
66. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

- i. **Market share:** The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Demand					
Imports from China	MT	0	10156	10491	8498
Imports from Other Countries	MT	105	898	773	2435
Domestic Industry Sales with captive	MT	450805	550008	538075	536140
Other Producer Sale	MT	547682	498119	496256	594166
Total Demand	MT	998593	1059181	1045595	1141239
Market Share in Demand					
China	%	0%	0.96%	1.00%	0.74%
Other Countries	%	0%	0.08%	0.07%	0.21%
Domestic Industry Sales	%	45%	51.93%	51.46%	46.98%
Other Producers Sales	%	55%	47.03%	47.46%	52.06%

As is clear from the above table, imports of the subject goods from subject country are insignificant in so far as the market share of the subject country in relation to demand is concerned.

The demand in India shown by the DI (As shown in the above table) in its submission does not include the data/figures of captive production by other domestic producers including supporters. Therefore, the demand in India as shown by the DI in its petition falls short of being conclusive.

- ii. **Profitability and Return on Investment:** It is noted that the losses of domestic industry reduced in the POI as compared to the previous years. The other indicators relating to profitability show improvement.

Particulars		2013-14	2014-15	2015-16	POI
Profit & Loss	Rs. /MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	-100	-71	-140	-44
Profit & Loss	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	-100	-86	-163	-54
Depreciation	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	182	144	108
Cash Profit	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	-100	21	-184	6
Capital Employed	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	-100	-123	-81	-83
Return on Capital Employed	%	****	****	****	****
Trend	Indexed	-100	-68	-215	-45

- iii. **Production and Capacity Utilization:** It is noted that the production of the Domestic Industry has increased in the POI to cater the increased demand. Domestic industry has closed one of its manufacturing facilities and production stopped in other two plants. The capacity of the Domestic Industry has therefore, decreased during the injury period. During the injury period, capacity utilization of domestic industry remained more or less same.

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Capacity	MT	811000	763000	690000	690000
Trend	Indexed	100	94	85	85
Production	MT	585354	701750	633262	641710
Trend	Indexed	100	120	108	110
Capacity utilization	%	72.18%	91.97%	91.78%	93.00%
Trend	Indexed	100	127	127	129

- iv. **Sales Volumes:** Sales of the domestic industry has improved as compared to the base year and domestic selling price has shown a decline due to the reduction in cost of sales of the domestic industry. Details of the sales volume and sales value are given in the Table below:

Particulars		2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic Sales Volume	MT	450805	550008	538075	536140
Trend	Indexed	100	122	119	119
Domestic Sales Price	Rs. /MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	89	72	74

- v. **Inventories:** The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Stock	MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	108	98	100
% of Sales	%	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	108	98	100

It is noted from the above that the average stock of the Domestic Industry has remained more or less same during the injury period.

- vi. **Employment and Wages:** The position with regard to employment and wages is as follows:



Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
No. of Employees	No.	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	100	105	103
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	118	131	132
Wages per Employee per annum	Rs.	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	118	125	128

It is noted from the above table that the numbers of employees engaged by the Domestic Industry has remained more or less same during the injury period. However, their wages increased during the same period.

- vii. **Productivity:** It can be seen from the table below that productivity in terms of production per employee has increased in the POI as compared to the base year.

	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production (MT)	MT	585354	701750	633262	641710
Employees	No.	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	100	105	103
Production/employee	MT/No.	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	120	103	106

From the above, it is noted that the productivity of the domestic industry has consistently increased over all the years of the injury period as compared to the base year.

- viii. **Magnitude of Dumping:** Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin determined against subject country is above *de minimis*.
- ix. **Ability to raise Capital Investment:** As per the annual report of the domestic industry it is stated that the DI has the ability to raise long term resources from global financial market at very competitive rates.
- x. **Factors affecting domestic prices:** The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. It is also noted that the landed value of subject goods from subject country is below non injurious price and selling price of the domestic industry.
- xi. **Growth:** As can be seen from the table in para 66(ii), cash loss to the tune of Rs.11,959 Lacs in the base year has turned into cash profit to the tune of Rs.754 Lacs during the POI which shows that the Domestic Industry has shown improvement with respect to the parameters relating to growth

### C. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

67. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

#### **Volume and prices of imports from third countries**

68. During POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country are not significant in volume. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry. Also, the subject goods from subject country are imported during the POI duty free under Advance Authorization Scheme but the DI has shown consistent loss during the injury period.

**Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.**

69. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

**Developments in technology:**

70. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is also not a factor causing injury to the domestic injury.

**Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

71. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

**Export performance of the domestic industry**

72. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

**Productivity of the Domestic Industry**

73. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.
74. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors.

**D. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY****Views of the Domestic Industry**

75. The following are the submissions relating to the likelihood of dumping and injury made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- The exporters in the subject country have huge production and surplus capacities of the subject goods. Further, the excess capacity available with such exporters is in itself many times the total production capacity of the Domestic Industry. The production capacity and surplus capacity considered from international journal PCI Wood Meckenzie is mentioned as below:

Capacity in China	27970000
Estimated exportable capacity	9110000
Capacity of Domestic Industry	690000
Estimated Indian Production	2235632
Production of Domestic Industry	641710
Sale of Domestic Producers	1130306
Sale of Domestic Industry	536140
Capacity as % of total domestic production in India	1251%
Capacities in China as % of domestic sales of all domestic producers	2475%
Exportable Surplus Capacity as % of total domestic production in India	407%
Exportable Surplus Capacity as % of domestic sales of all domestic producers	806%

Recently Turkey has levied the anti-dumping duties on the subject goods from China. This clearly establishes that the Chinese exporters have indulged in dumping practices not only in India but also in other countries.

- The fact that the Chinese exporters continue to indulge in dumping practices is proven by their current prices to India. Further, the fact that they continue to indulge in dumping in other important markets is proved by the fact that anti-dumping duties have been imposed by other countries on Chinese exports.

- iii. Despite non-cooperation of the Chinese exporters, the Domestic Industry was able to get the information which proves the export orientation of the Chinese exporters. The data obtained from the website of CCF group shows that the export quantity has doubled between 2013 -2018. The examination of the data of the other Chinese exporters would also show the similar trend. However, it is for this very reason that the Chinese exporters decided not to cooperate in the present investigation.
- iv. It is a matter of fact that China controls about 75-80% of the world production of the subject goods. Such an overwhelming capacity/production allows them to disturb the markets around the world including India.
- v. Almost 90% of the capacities added throughout the world in the last five years have come up in China. Such expansion coupled with the decline in demand in China has made other countries more vulnerable.
- vi. Further, the total production of the subject goods itself exceeds the domestic demand in China by around 50% of Indian production. Therefore, there is clear that likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event the anti-dumping duties are not continued.
- vii. Indian market is attractive to the Chinese exporters as India constitutes the biggest market outside China constituting more than 30% of the market of the rest of the world.
- viii. The existence of current dumping and injury margins in itself establish that the Domestic Industry is destined to suffer greatly if the current anti-dumping duties are revoked.

**Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties**

76. The following are the likelihood of dumping and injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation:
  - i. Having mere capacity is not sufficient to prove likelihood of injury. The applicant is required to prove that the existence of such surplus capacity with the exporters would result in dumping of products in India. However, the applicant failed to prove any such allegation and hence such an allegation does not stand the qualified evidence under the likelihood parameter.
  - ii. The analysis in the present case would be incomplete without a detailed analysis of the likelihood of the existing capacities in China vis-à-vis their likelihood of entering the Indian market.
77. The Authority has examined the contention of the Domestic Industry to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

**Level of current and past dumping margin**

78. It is noted that the level of dumping margin is significant but the quantum of imports from the subject country is insignificant both in the original as well as present investigation.

**Volume of Imports during post POI**

79. It is noted from the DGCI&S data that the imports from subject country have remained insignificant as compared to the demand in India even during the post investigation period.

Country	Imports during POI (MT)	Imports post POI (MT)
China	8498	10407 (Annualized)

**Price attractiveness of Indian market**

80. The price, at which the subject goods are being exported by subject country to India, is more or less same if compared with the prices at which the subject country is exporting to other countries which indicates that Indian market is more or less at the same level as other countries are. Therefore, the Authority holds that there is, as such no, price attractiveness of the Indian market.

**Huge Production Capacity in subject country**

81. As per the information furnished by the Domestic Industry, the producers of subject goods in the subject country maintain huge capacities. Domestic Industry has provided evidence of huge production capacities with various

manufacturers in subject country. However, it was found by the Authority that there are other countries like Turkey and Egypt which absorb the major proportion of the Chinese exports.

**Export orientation of the exporters from subject country**

82. The petitioner has stated that the exporters in the subject country are majorly export oriented. It has also been contended that in the event of cessation of duty, these exporters are likely to divert their exports to India at dumped prices. It is also submitted by the DI that the subject country has huge surplus capacity which is not in proportion to the domestic demand in the subject country. Therefore, the exporters are reliant on the exports to utilize their capacities. Further, the fact that some of the other major global users of POY have already imposed anti-dumping duty on exports from China, substantiates the claims of the domestic industry. However, it was found by the Authority that there is no export orientation of Chinese exports as its exports accounts for only 3,57,808 MT out of its unutilized capacity to the tune of 91,10,000 MT during the POI.

**Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market**

83. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration.
84. It is pertinent to note that no exporter has participated in the present investigation and the major contentions of the Domestic Industry, disputed by other interested parties, have been duly addressed in this Final Findings.

**Post Disclosure submissions by the Domestic Industry**

85. That the presence of current dumping and injury is a robust factor for continued imposition of duties world-wide. It is also submitted that the current high levels of dumping margin and injury margin, is sufficient enough to indicate the need for continued protection to the Indian industry from admittedly export oriented nature of the Chinese producers and exporters.
86. That the analysis carried out by the Authority relating to injury parameters like price undercutting and price underselling, price suppression clearly show the adverse impact of dumped imports on the performance of the Domestic Industry.
87. In relation to the observation of the Authority that “price undercutting from China is insignificant at aggregate level”, it is submitted that price undercutting cannot be considered in isolation and is always considered along with price underselling and price suppression/depression. Since subject goods are suppressing/depressing the Domestic Industry prices, it would be completely inappropriate to consider price undercutting without reference to the price underselling and suppressing/depressing effect of imports.
88. It may also not be out of place to mention that none of the exporters has cooperated in the investigations. In the absence of the detailed transaction-wise data from the exporters, the price undercutting analysis at the aggregate level loses its significance considerably. It would be a travesty of justice if the exporters are rewarded for their non-cooperation with the Authority.
89. In relation to decline in imports, it is submitted that the Chinese exporters tactfully created this dip in imports to mislead the Authority in believing that there is no volume pressure from the Chinese exports.
90. In relation to raise ability to raise Capital Investment, it is submitted by the domestic industry that the annual report of the Domestic Industry is for the performance and expectations of the company as a whole, while the present investigation is concerned with the subject goods only. However, the ability of the Domestic Industry to raise capital investment in the context of the subject goods will get seriously marred in case the duties are discontinued. Therefore, in the event the duties are revoked the POY sector in India is destined to hit the base.
91. In relation to price attractiveness for the Chinese producers, Domestic Industry submitted that in the absence of any response from Chinese exporters, non-availability of information relating to likelihood cannot be held against Domestic Industry. It is reiterated that the Chinese producers very strategically did not participate in the present investigation because their data would have established that they are export reliant and are dumping heavily in the Indian market as well as other markets.

92. That the contention of some importers that the continued imposition of the duties in this case would adversely affect the public interest is happening under advance authorization, it would be incorrect to state that the continued imposition of duties would affect the public interest adversely.
93. That the Chinese exporters should not be rewarded for their non-cooperation and duties should not be discontinued in the absence of data relating to exportable surplus capacity. Therefore, Domestic Industry requested that the non-cooperation of the Chinese exporters should not be allowed to be a means of undue and unwarranted benefit to them.
94. The fact that as the prices of Chinese exports to India and to third countries remain comparable clearly indicates that in the event of revocation of duties, imports from China will come at these prices only and will definitely worsen the condition of POY industry in India.
95. That there is significant current dumping margin and injury margin, likelihood of injury and dumping is imminent and therefore, the present investigation is fit for continued imposition of duties. Thereby, requesting the Authority to kindly confirm the continued imposition of duty on the subject goods originating in or exported from China.

**Post Disclosure Statement submissions by other interested parties**

96. Domestic Industry has failed to provide methodology of segregating of import data between PUC and non-PUC. They have requested that the Authority should provide segregation of import data in the final findings.
97. Applicants only accounts for 28% of the total production and any likelihood analysis based on such small share would not provide correct results. It was also pointed out that in one of the recent final findings, the Authority has terminated the investigation only because applicants accounts for mere 27% of the total production in India.
98. It is also contended by the interested parties that the financial health of the Domestic Industry does not reflect the wider industrial health of the Indian domestic producers as a whole. Therefore, they requested terminated of the investigation or alternately, the DI must be redefined to include a wider segment of POY producers in India.
99. The Authority has failed to assess the impact of the anti-dumping duties with respect to POY on other products, such as texturized yarns. In this regard, the Authority's simplistic observation that it is only concerned with the PUC regardless of the impact on other products and industries cannot be accepted.
100. The Authority has to record the rationale and methodology followed by it in the construction of normal value and export price. We request the Authority to include the methodology, beyond the simpliciter "on the basis of best available information.
101. Imports from China are negligible as compared to production and demand in India and therefore, imports from China cannot be held responsible for any injury to Domestic Industry.
102. Domestic Industry with other domestic producers accounts for 99% of the demand and imports from China accounts for mere 1%. Therefore, no injury can cause to Domestic Industry.
103. The Respondents reiterate that the dumping margin is constructed by the Authority and is not reflective of actual data of any producer or exporter and therefore, cannot form the basis of injury assessment in any manner.
104. Excessive capacities are not sufficient for determination of likelihood of recurrence or continuation of injury to the domestic industry. The Authority must complete its assessment to examine whether there is any excess capacity which may lead to dumping of imports specifically into India.
105. Domestic Industry is performing well with respect to all economic parameters like the production, the capacity utilization and the domestic sales have improved. Domestic Industry has also maintained its inventories at the same level despite increased production.
106. There is no price attractiveness of the Indian market as the prices of Chinese exports to India and to third countries remain comparable, there is no evidence that the alleged production capacities are in excess of the demand for Chinese products or that the export orientation has ever led to a situation of substantial supply to India.

107. There is no continuing injury and nor is there any likelihood of recurrence of dumping or injury in the facts and circumstances of the present case.

#### **Examination by the Authority**

108. The Authority notes that most of the submissions by parties are of repetitive nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above deals with all such arguments of the interested parties including Domestic Industry. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:
- a. In relation to the submissions relating to segregation of import data, it is noted that the Authority has called for the import data from DGCI&S for the injury period and Post-POI. Further, the Authority had segregated the import data based on the description of the PUC.
  - b. After looking at price undercutting, price underselling, price suppression / depression and the injury suffered by the Domestic Industry together, it is noted that despite having no competition from the subject goods imported from China (as imports are coming in India under advance authorization), the financial performance of the Domestic Industry did not improve. Since current losses or the injury caused cannot be attributed to the dumped imports of subject goods, the possibility of their likelihood to cause injury to Domestic Industry is unforeseeable.
  - c. In relation to submissions of the Domestic Industry that non-participation of Chinese exporters cannot be held against them, it is noted that in fact, the Authority in the first Sunset Review, despite no participation from any exporter, extended the duties after finding the likelihood of dumping and injury. In addition, the export orientation of Chinese exporters towards the world has been found to be negligible as China exported only 3,57,808 MT out of its unutilized capacity to the tune of 91,10,000 MT during the POI. Moreover, the analysis of the Chinese exports shows that countries like Turkey (even after the imposition by Turkey of the anti-dumping duty on China) and Egypt are the major absorbers of the Chinese exports of the subject goods to the world. Therefore, it is clearly visible that other export markets are available to absorb additional Chinese exports, if any.
  - d. In relation to submissions relating to price attractiveness of the Indian market, it is noted that the price, at which the subject goods are being exported by subject country to India, is more or less same if compared with the prices at which the subject country is exporting to other countries which indicates that Indian market is more or less at the same level as other countries are. Therefore, the Authority holds that there is no, as such, price attractiveness of the Indian market.

#### **Conclusion**

109. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes as below:
- i. Domestic Industry suffered continuous injury even during the period when there was no or insignificant imports of subject goods from the subject country. Therefore, the injury cannot be attributed to dumped imports.
  - ii. Domestic Industry was not able to justify the price attractiveness of Indian market and export orientation of Chinese exporters.
  - iii. Evidence on record do not indicate that the dumped imports from China will lead to injury to Domestic Industry.
  - iv. Domestic Industry failed to substantiate its claim in relation to likelihood of injury to the domestic industry due to the cessation of Anti-Dumping duty in force.

#### **Recommendation**

110. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to domestic industry, exporters, importers, users and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the

investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Act and Rules, the Authority holds that Domestic Industry failed to provide any satisfactory evidence that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry due to reasons and/or analysis given above. Therefore, the Authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR.

SUNIL KUMAR, Add. Secy. & Designated Authority